मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha1987@gmail.com
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

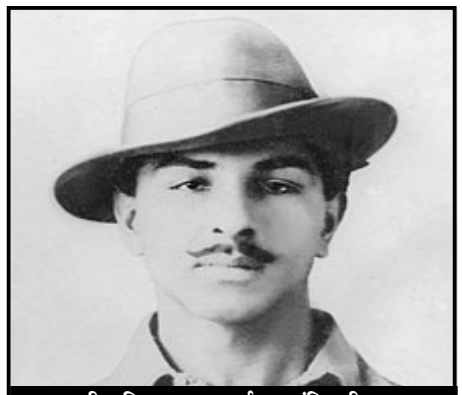

शहीद दिवस 23 मार्च : क्रांति की धार विचारों की सान पर तेज होती है - भगत सिंह

कांग्रेस अभी भी घुर-घुर मोड में 3
मोदी की चलती है नेहरू की गलती है 4
बनारस में उजाड़ी दलित बस्ती 5
मोदी के अधूरे वादे 6
खट्टर ने भाड़े पर कराया सत्कार 8

वर्ष 35 अंक -18 फ़रीदाबाद 17-23 मार्च 2019 फोन - 9999595632 2.50 ₹

मोदी की विदेश यात्रा पर 7266 करोड़ खर्च, बीएसएनएल के 1.76 लाख कर्मचारियों के वेतन को पैसे नहीं....

सरदार पटेल की मूर्ति की रखवाली करने वालों को चार महीने से वेतन नहीं.....

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

नई दिल्ली: जिस भारत नामक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा पर 7266.94 करोड़ खर्च किए जाते हों, उसी देश में सरकारी कंपनी बीएसएनएल के 1.76 लाख कर्मचारियों को इस महीने फरवरी का वेतन नहीं मिला। मजे की बात तो यह है कि इनमें से करीब 80 हजार कर्मचारी ठेकेदारी में हैं। हालांकि कई और विभागों में भी वेतन को लेकर संकट के दिन हैं लेकिन बीएसएनएल के कर्मचारी इतने ज्यादा हैं कि इस पर सभी का ध्यान गया। बीएसएनएल के कर्मचारियों का दिसंबर का वेतन 5 जनवरी को बंटा था। जनवरी की सैलरी 21 फरवरी को देने की घोषणा की गई। मोदी सरकार ने अब बीएसएनएल से कहा है कि अपनी संपत्तियां बेचकर वेतन दो। इसके साथ ही बीएसएनएल के विनिवेशीकरण की तैयारी भी हो रही है और मुकेश अंबानी की कंपनी जियो की नजर इस पर बराबर बनी हुई है। जियो को उपहार में देने के लिए भी इस कंपनी को प्रबंधन के स्तर पर पंगु बनाया जा रहा है।

सुनियोजित साजिश

बीएसएनएल गुहार लगा रहा है कि कर्मचारियों का वेतन देने के लिए उसे बैंक से कर्ज लेने की छूट दी जाए, लेकिन दूरसंचार विभाग (डॉट) में उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। डॉट ने गैरकानूनी तरीके से बीएसएनएल को अपनी संपत्तियां ट्रांसफर की हैं, इसलिए इन संपत्तियों पर कोई कर्ज नहीं मिलने वाला। ऐसे में बैंको को गारंटी डॉट को देनी चाहिए, क्योंकि बीएसएनएल कानूनी तौर पर कोई कर्ज नहीं मिल सकता।

जीपीएफ का अता-पता नहीं

बीएसएनएल कर्मचारियों के जीपीएफ का पैसा भी समय से नहीं जमा करा रहा है। बीएसएनएल को यह पैसा हर माह के आखिर में डॉट के पास जमा कराना होता है। जीपीएफ में जमा पैसे पर सरकार 8 से 8.5 फीसदी तक ब्याज देती है। लेकिन बीते तीन-चार

माह से जीपीएफ का पैसा ही नहीं जमा कराया गया है। ऐसे में कर्मचारियों को जीपीएफ पर मिलने वाले ब्याज का भी घाटा हो रहा है।

बीएसएनएल जो भी पैसा कमा रहा है उसका इस्तेमाल राजस्व मद में हो रहा है, और बीएसएनएल की क्षमता को बेहतर करने के लिए कोई पैसा खर्च नहीं किया जा रहा है। बीएसएनएल में कुप्रबंधन को इसी से समझा जा सकता है कि दक्षिण के जिन सर्किल, खासतौर से केरल से उसे मुनाफा हो रहा था, लेकिन इन सर्किल को सरकारी कंपनी ने बैंकों के पास गिरवी रख दिया है। और अब हालत यह है कि बैंको का ब्याज चुकाने तक के पैसे उसके पास नहीं हैं।

बीएसएनएल के अफसरों का कहना है कि, एक तरफ तो सीएमडी सार्वजनिक तौर पर बीएसएनएल को उबारने की योजना और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की बात करती हैं, लेकिन होता उसका बिल्कुल उलटा है। बीएसएनएल के कुल खर्च में करीब 55 फीसदी वेतन मद में जाता है। वहीं हाल के दिनों में बीएसएनएल के राजस्व में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। अफसरों का कहना है कि जब तक बीएसएनएल में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश नहीं किया जाएगा, इसके दिन नहीं फिरेंगे।

मैनेजमेंट का वेतन नहीं रुकता

कंपनी के शीर्ष प्रबंधन को तो समय पर वेतन मिल रहा है लेकिन डेढ़ लाख से ज्यादा कर्मचारियों के वेतन का भुगतान रुका हुआ है। तमाम शिकायतों के बाद भी शीर्ष प्रबंधन को नहीं बदला जाना एक सियासी साजिश की तरफ इशारा करता है।

अधिकारी और कर्मचारी बताते हैं कि, बीएसएनएल को अभी तक 4जी स्पेक्ट्रम नहीं दिया गया है। सरकार की तरफ से भी इस बात की कोशिश नहीं हो रही है कि बीएसएनएल में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए निवेश किया जाए।

...और अब विनिवेश की तैयारी

बीएसएनएल का कुल घाटा 31287 करोड़ है। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्रा पर यह देश 7266.94 करोड़ रुपये खर्च करता है। ...और वही प्रधानमंत्री, वही मोदी अब बीएसएनएल का विनिवेश या नाश करना चाहता है।हाल ही में दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन ने बीएसएनएल के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की है. बैठक में बीएसएनएल के अधिकारियों को इसे बंद करने पर विचार करने के लिए कहा गया है।

बैठक में बीएसएनएल के चेयरमैन अनुपम श्रीवास्तव ने एक प्रेजेंटेशन पेश किया था। इस प्रेजेंटेशन में कंपनी की वित्तीय हालत, घाटा और रिलायंस जियो की एंट्री के बाद उसके कारोबार पर कितना असर पड़ा, इसका लेखा-जोखा था। इसके अलावा कर्मचारियों के वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम (वीआरएस) और समय से पहले रिटायरमेंट प्लान का भी प्रेजेंटेशन दिया गया।

विनिवेश नहीं तो कंपनी बंद करने पर विचार

सरकार एक तरफ बीएसएनएल के विनिवेश की तैयारी कर रही है। वहीं, अब कंपनी से कारोबार को बंद करने पर विचार करने को कहा है। सरकार ने बीएसएनएल से तमाम विकल्पों पर विचार करने को कहा है। सूत्रों के मुताबिक, बीएसएनएल को 3 विकल्पों पर विचार करना है। इनमें पहला कंपनी में रणनीतिक विनिवेश, दूसरा कंपनी का कारोबार बंद करना और तीसरा वित्तीय सहायता के साथ कंपनी को दोबारा मजबूत बनाना शामिल है।

कर्मचारियों की उम्र घटाने का हथकंडा

बीएसएनएल ने अपनी प्रेजेंटेशन में कहा है कि दूसरी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा के अलावा उनकी बड़ी चुनौती बड़ी संख्या में उसके कर्मचारी हैं। कर्मचारियों की संख्या कम करने के लिए वीआरएस और रिटायरमेंट की उम्र को 60 से घटाकर 58 करने का भी विकल्प दिया गया गया है। कंपनी के मुताबिक, अगर वर्ष 2019-20 से रिटायरमेंट उम्र घटा दी जाती है, तो इससे कंपनी को वेतन के मद में 3,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है।

टारगेट पर 67 हजार कर्मचारी

बीएसएनएल के मुताबिक, वीआरएस के जरिए 56-60 साल के कर्मचारियों को टारगेट किया जाएगा। इस उम्र वर्ग में करीब 67 हजार कर्मचारी हैं। कंपनी का कहना है कि अगर इनमें से 50 फीसदी यानी करीब 33846 कर्मचारियों को भी वीआरएस दिया जाता है तो इससे भी वेतन में 3 हजार करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इसके अलावा विभिन्न मदों में अनुग्रह राशि 6,900 करोड़ रुपए से 6,300 करोड़ रुपए हो सकती है।

मुद्रीकरण का भी सुझाव

बीएसएनएल ने मुद्रीकरण का भी सुझाव दिया है। इसमें बीएसएनएल की बड़ी जमीनों और बिल्डिंग्स को बेचकर 15 हजार करोड़ रुपए जुटाया जा सकता है। कंपनी ने कहा कि यह काम अगले दो से तीन साल में डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऐंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट (डीआईपीएएम)की ओर से किया जा सकता है।

शेष पेज चार पर

सरकारी स्कूल में बच्ची से रेप: केवल चौकीदार गिरफ्तार

फ़रीदाबाद (म.मो.) बीते मंगलवार शहर के एक सरकारी स्कूल में 11 साल की बच्ची से स्कूल के चौकीदार ने रेप किया। सूचना मिलने पर महिला थाना एनआईटी ने मुकदमा दर्ज करके चौकीदार को गिरफ़्तार कर के अदालत में पेश कर दिया जहां से उसे जेल भेज दिया गया और हो गयी मामले की इतिश्री।

सुधी पाठक भूले नहीं होंगे कि करीब डेढ वर्ष पूर्व गुड़गांव के एक निजी स्कूल में एक बच्चे की हत्या स्कूल के ही दूसरे बड़े बच्चे ने कर दी थी। उस केस में पुलिस ने स्कूल बस के कंडक्टर को जबरन दोषी बना कर गिरफ़्तार व टार्चर कर के जेल भेज दिया था। उसी केस में राज्य सरकार ने न केवल स्कूल के प्रिंसिपल को दोषी ठहराया बल्कि मुंबई में बैठे स्कूल मालिकान को भी लपेट लिया था। उनकी हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट तक खूब खिंचाई हुई। उसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा गरजी-बरसी थी। सरकार को इस सम्बन्ध में

गाइड लाइन बनाने के आदेश भी दिये थे। परंतु आज तक यह पता नहीं कि वे गाइड लाइन कहां हैं, किसके पास हैं और वे क्या काम आ रही हैं ?

सरकारी स्कूल में हुए उक्त रेप कांड का मामला कोई एक दिन का नहीं है। बच्ची के साथ यह काम पिछले कई दिनों से हो रहा था और वह भी स्कूल परिसर में बने चौकीदार निवास में। सवाल यह पैदा होता है कि स्कूल में तैनात प्रिंसिपल व अन्य स्टाफ़ क्या कर रहा था ? बच्ची की क्लास टीचर कैसे इतनी लापरवाह हो सकती है कि उसकी क्लास की एक बच्ची क्लास से गायब रहे, उसके साथ रेप होता रहे और उसको पता तक न चले। इस बार भी रेप का पता घर वालों को तब चला जब घर पहुंचने पर बच्ची की तबियत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गयी।

एक स्थिति यह भी हो सकती है, जो आज अधिकतर सरकारी स्कूलों की है, कि वहां न तो पर्याप्त स्टाफ़ हो और न ही प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के नाम पर आज-कल एक ही प्रिंसिपल को एक से अधिक स्कूलों का चार्ज दे दिया जाता है, जाहिर है ऐसे में प्रिंसिपल किसी भी स्कूल में अपने दायित्व को भली-भांति निभाने में असमर्थ होता है।

ऐसे में पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की बनती है। इसलिये चौकीदार के साथ-साथ स्कूल शिक्षा के उच्चतम अधिकारियों, शिक्षा मंत्री व मुख्यमंत्री को भी इस केस में नामजद दोषी बनाया जाना चाहिये, तभी सरकारी स्कूलों में होने वाली हत्यायें व बलात्कार थम सकेंगे।

मुख्य न्यायाधीश गोगोई: सीबीआई डायरेक्टर शुक्ला को कानून ने लगाया है!

दिल्ली (म. मो.) प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी का बस चलता तो सीबीआई डायरेक्टर एक अन्य मोदी ही होता। यह मोदी कोई और नहीं जींद, हरियाणा का निवासी और वर्तमान में एनआईए डायरेक्टर का पद संभाल रहा व्यक्ति ही है। इन मोदी साहब (पूरा नाम- योगेश चन्द्र मोदी)की खासियत यह है कि इनका परिवार दो पीढ़ियों से आरएसएस में सक्रिय रहा है। प्रदेश की खट्टर सरकार ने इस मोदी के बड़े भाई यशपाल सिंघल को हरियाणा का डीजीपी बनाया था, लेकिन जाट आरक्षण आन्दोलन में सरकार की इतनी भद्द पिटी कि उन्हें हटाना पड़ा।

सवाल है कि नरेंद्र मोदी भला इन मोदी को ही सीबीआई चीफ बनाने पर क्यों उतारू थे और बावजूद उनके जोर लगाने के ये साहब बन क्यों नहीं सके। कौन नहीं जानता कि सीबीआई को हर प्रधानमन्त्री अपने निजी और राजनीतिक हितों में इस्तेमील करता रहा है। नरेंद्र मोदी ने तो सारी हदें पार कर दीं और इस चलते पिछले डायरेक्टर आलोक वर्मा और उनके डिप्टी राकेश अस्थाना के बीच खूब जूत बजे थे और वह भी सार्वजनिक रूप से। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बावजूद प्रधानमन्त्री और उनके एनएसए अजित डोभाल ने अपने दरबारी अस्थाना के पक्ष में हर उल्टा-सीधा काम किया। अंत में वर्मा और अस्थाना दोनों को सीबीआई से विदा होना पड़ा था।

जाहिर है प्रधानमन्त्री और एनएसए को नए सीबीआई डायरेक्टर के रूप में अस्थाना की टक्कर के दरबारी की जरूरत थी। योगेश मोदी में ये सारे गुण थे। जबकि अस्थाना ने नरोदा पाटिया हत्याकांड में नरेंद्र मोदी के मुताबिक उस त्रासदी के सूत्र जबरदस्ती अल-कायदा से जोड़ दिए थे, योगेश मोदी ने नरेंद्र मोदी के विरोधी गुजरात के पूर्व गृह मंत्री हरेन पांड्या के कत्ल में फर्जी लोगों का चालान कर अमित शाह और नरेंद्र मोदी को साफ बचाया था। ऐसा भक्त पुलिस अधिकारी जो आका के लिए रात को दिन कर सकता हो, अन्यथा कहाँ मिलता!

लिहजा योगेश मोदी की ताजपोशी की तैयारी पूरी थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश गोगोई के चयन समिति की दो दिन तक चली अंतिम बैठकों में वरीयता के पैमाने को लागू करने पर अड़ जाने से सारी तैयारी धरी की धरी रह गयी। हुआ यह कि मध्य प्रदेश कैडर के ऋषि कुमार शुक्ला वरीयता क्रम में सबसे ऊपर थे और उनकी नौकरी भी अभी दो वर्ष से अधिक बाकी थी। प्रधानमन्त्री ने लाख चाहा लेकिन गोगोई ने वरीयता क्रम तोड़ने से साफ मना कर दिया। झख मार कर नरेंद्र मोदी को शुक्ला के नाम पर हाँ करनी पड़ी।

कहते हैं कि पद भार ग्रहण करने के बाद शुक्ला चयन समिति के तीनों सदस्यों से औपचारिक मुलाकात के लिए गए। लोकसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी पार्टी कांग्रेस का स्वार्थ (रोबर्ट वाड्रा) ध्यान में रखते हुए उनसे मिलना ही ठीक नहीं समझा। प्रधनमंत्री ने उनसे कहा कि आपने एक बेहद गंदे हो चुके संगठन का जिम्मा लिया है। काश वे यह कहने की हिम्मत भी कर पाते कि सीबीआई को गन्दा करने में स्वयं उनकी भी खासी भूमिका रही है।

मुख्य न्यायाधीश गोगोई ने शुक्ला से कहा कि उन्हें कानून ने सीबीआई का डायरेक्टर बनाया है और उन्हें कानून की पालना करनी चाहिए न कि किसी अन्य शक्ति केंद्र की। स्पष्ट ही गोगोई का इशारा प्रधानमन्त्री मोदी और उनके एनएसए डोभाल की और था। गोगोई को नवम्बर में रिटायर होना है और तब तक शुक्ला के पास कुछ कर गुजारने का अवसर है। राजनीतिक कलाबाजों से स्वतंत्र होकर ही वे सीबीआई को खोयी साख वापस लाने की दिशा में कुछ कर पायेंगे।